



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27—फरवरी 2, 2018 (माघ 7, 1939)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2018 (MAGHA 7, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

पंजाब नैशनल बैंक
(प्रधान कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसंबर 2017

सं.प्र.का.:पेंशन:विविध 2017—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम 2017 कहलाएंगे।
(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (इसके बाद कहे गये विनियमों के रूप में संदर्भित), —
विनियम 2, के खंड (एस) में उपखंड (सी) के बाद निम्नांकित उप खंड जोड़ा जाए, अर्थात्:-
(डी) मई 2005 के प्रथम दिवस या उसके बाद सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त या मृत्यु होने पर किसी कर्मचारी के संबंध में, बैंक में अपनी सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान कर्मचारी द्वारा आहरित, नियत वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन, यदि कोई हो, और विशेष वेतन, स्नातक वेतन, व्यावसायिक योग्यता वेतन, नियत कार्मिक वेतन का वेतन वृद्धि घटक और स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो,:

परंतु 01 मई 2005 से प्रभावी इस खंड के प्रावधानों में अप्रैल 1998 के प्रथम दिवस पर या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 से पहले सेवा में सेवानिवृत्त या मृत्यु हो जाने वाले किसी कर्मचारी के संबंध में प्रभाव पड़ेगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) (क) अधिसूचित तिथि के बाद और 31 मार्च 2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा में सेवारत हो:”

(ख) उप-विनियम 10 के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् :-

- (11) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे और 27 अप्रैल 2010 तक बैंक की सेवा में सेवारत रहे हों, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;
- (12) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे तथा उस तिथि से और 27 अप्रैल 2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;
- (13) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए और मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;
- (14) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे, और उस तिथि के बाद बैंक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार, पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;

4. उक्त विनियमों के विनियमन 28 में, प्रावधानों के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण 29 सितम्बर 1995 को या उसके बाद सेवा में नहीं थे, लेकिन 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत इस संबंध में बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार एवं सरकार द्वारा अनुमोदित, योजना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन पेंशन फंड में शामिल होने के हकदार होंगे।”

5. उक्त विनियमों के विनियमन 36 में, -

(क) खंड (सी) में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु 1 मई 2005 को, या से, अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके पश्चात, परंतु 31 अक्टूबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उनकी न्यूनतम पेंशन एक हजार साठ रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके बाद, सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की तीन सौ पचपन रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ तीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ पंचानवे रुपये प्रतिमाह होगी।

(ख) खंड (सी) के बाद निम्नलिखित खंड (डी) शामिल किया जायेगा, अर्थात् :-

(डी) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार चार सौ पैंतीस रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की चार सौ अस्सी रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ बीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार अस्सी रुपये प्रतिमाह होगी।

परंतु 1 मई 2005 के प्रथम दिवस से, इस खंड के प्रावधान अंशकालिक कर्मचारी सहित किसी भी कर्मचारी पर लागू होंगे, जो 1 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए।

(ई) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो नवम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार सात सौ उन्नीस रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो नवम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ पंचानवे रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की आठ सौ बानबे रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार तीन सौ उन्तालिस रुपये प्रतिमाह होगी।

(6) उक्त विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियम (4) में,-

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (III) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

‘परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसे कि शब्दों “छह हजार सात सौ छप्पन” को शब्द “सात हजार और चालिस” से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैंसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

‘परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसे कि शब्दों “छह हजार सात सौ छप्पन” को शब्द “सात हजार और चालिस” से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैंसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

‘परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसे कि शब्दों “तीन हजार तीन सौ अठत्तर” को शब्द “तीन हजार पाँच सौ बीस” से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल चार हजार सात सौ तिरासी रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल पाँच हजार नौ सौ अठाइस रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(7) उक्त विनियमों के विनियम 48 में, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“48. बैंकों को हुई आर्थिक हानि की वसूली:-

(1) यदि पेंशनभोगी अपनी सेवा की अवधि के दौरान किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में घोर कदाचार या लापरवाही या आपराधिक न्यासभंग या जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य का दोषी पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसका अंश रोक सकता है या आहरित कर सकता है, चाहे स्थायी रूप से या निर्धारित अवधि के लिये, और बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या अंश को पेंशन से वसूल करने के आदेश दे सकता है।

परंतु कोई भी अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जायेगा।

परंतु जहां पेंशन के एक अंश रोक दिया गया है या आहरित किया गया है, पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन की रकम इन विनियमों के तहत देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी:

परंतु यह भी कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात्, विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी की सेवा में रहते हुए आरंभ की गई है, इन विनियमों के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी तथा प्राधिकारी द्वारा वह आरंभ की गई थी वह उसी प्रकार से जारी रखी जायेगी तथा समाप्त की जायेगी मानो कर्मचारी सेवा में है।

(2) यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी, तो ऐसे संस्थापन के चार वर्ष पूर्व हुई किसी भी घटना के मामले में कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जायेगी।

परंतु इस प्रकार आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही, कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही के लिये लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहाँ वसूली सामान्यता कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जायेगी”।

8. उक्त विनियमों के विनियम 52 में:-

(ए) उप-विनियमन (1) के लिये, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(1) किसी कर्मचारी के संबंध में जहां विनियम 34 या विनियम 46 के प्रावधान लागू होते हैं, परिवार की पेंशन के अलावा एक पेंशन उस तारीख से देय होगी, जिस पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है।”

(बी) उप-विनियम (3) में निम्न प्रावधान को शामिल किया जायेगा :-

“परंतु 27 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने वाले को परिवार पेंशन सहित पेंशन 27 नवंबर 2009 से लागू होगी।”

9. उक्त विनियम के परिशिष्ट II में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

परिशिष्ट II
(विनियम 37 देखें)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगी :-

- (1) अधीनस्थ श्रेणी के जो कर्मचारी, 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात, परंतु 01 नवंबर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात परंतु 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर, यथास्थिति 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :-

| मूल पेंशन का वेतनमान | मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में प्रतिमाह महंगाई राहत की दर |
|--------------------------------|--|
| (1) | (2) |
| (i) रु. 1250/- तक | 0.67 प्रतिशत |
| (ii) रु. 1251/- से रु. 2000/- | रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 1250/- से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत |
| (iii) रु. 2001/- to रु. 2130/- | रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा रु. 2000/- से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत। |
| (iv) रु. 2130/- से अधिक | रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- और रु. 2000/- के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत। |

- (2) कामगार श्रेणी के जो कर्मचारी 01 नवंबर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर, यथास्थिति, प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :

| मूल पेंशन का वेतनमान | मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में प्रतिमाह महंगाई राहत की दर |
|--------------------------------|--|
| (1) | (2) |
| (i) रु. 2400/- तक | 0.35 प्रतिशत |
| (ii) रु. 2401/- से रु. 3850/- | रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 2400/- से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत। |
| (iii) रु. 3851/- से रु. 4100/- | रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत + रु. 3850 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत। |
| (iv) रु. 4100/- से अधिक | रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- और रु. 3850/- के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत। |

- (3) जो कर्मचारी 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :-

| मूल पेंशन का वेतनमान | मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में प्रतिमाह महंगाई राहत की दर |
|--------------------------------|--|
| (1) | (2) |
| (i) रु. 3380/- तक | 0.25 प्रतिशत |
| (ii) रु. 3381/- से रु. 5420/- | रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 3380/- से अधिक मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत। |
| (iii) रु. 5421/- से रु. 5770/- | रु. 3380/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत + रु. 5420 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत। |
| (iv) रु. 5770/- से अधिक | रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- और रु. 5420/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत। |

परंतु, 1 मई 2005 पर या से कर्मचारियों के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात लेकिन 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1684 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :-

| मूल पेंशन का वेतनमान | मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में प्रतिमाह महंगाई राहत की दर |
|--------------------------------|--|
| (1) | (2) |
| (i) रु. 3550/- तक | 0.24 प्रतिशत |
| (ii) रु. 3551/- से रु. 5660/- | रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 3550/- से अधिक मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत। |
| (iii) रु. 5661/- से रु. 6010/- | रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत + रु. 5650 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत। |
| (iv) रु. 6010/- से अधिक | रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- और रु. 5650/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत। |

- (4) 1 मई 2005 पर या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.18 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी:-

परंतु 1 मई 2005 पर या से, कर्मचारियों के संबंध में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई राहत इस खंड की शर्तों के अनुसार देय होगी :

परंतु 1 नवंबर 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.15 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी:-

- (5) महंगाई भत्ता पिछले वर्ष के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर पहली फरवरी से आरंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिये और उसी वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर और 01 अगस्त से आरंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिये देय होगा।
- (6) परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन और अनुकम्पा भत्ते के संबंध में महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगी।
- (7) पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राशि की अनुमति संराशीकरण के बाद भी दी जायेगी।
- (8) महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं हैं।
- (9) जिस पेंशनभोगी की मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है परंतु मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है, वह न्यूनतम पेंशन पर लागू महंगाई राहत आहरित कर सकेगा।
10. उपरोक्त विनियमों में परिशिष्ट III के लिये निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परिशिष्ट III
(विनियम 39 देखें)

परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

- (क) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था :-

| वेतनमान प्रतिमाह | मासिक परिवार पेंशन की राशि |
|----------------------|--|
| (1) | (2) |
| रु. 1500/- तक | ‘वेतन’ का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 375/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा। |
| रु. 1501 से रु. 3000 | ‘वेतन’ का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 450/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा। |
| रु. 3000 से अधिक | ‘वेतन’ का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 600/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 1250/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। |

- (ख) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था :-

| वेतनमान प्रतिमाह | मासिक परिवार पेंशन की राशि |
|----------------------|---|
| (1) | (2) |
| रु. 2870 तक | ‘वेतन’ का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 720/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा। |
| रु. 2871 से रु. 5740 | ‘वेतन’ का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 860/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा। |
| रु. 5740 से अधिक | ‘वेतन’ का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1150/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 2400/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। |

- (ग) 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में :-

| वेतनमान प्रतिमाह | मासिक परिवार पेंशन की राशि |
|----------------------|---|
| (1) | (2) |
| रु. 4040 तक | ‘वेतन’ का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1015/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा। |
| रु. 4041 से रु. 8080 | ‘वेतन’ का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1212/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा। |
| रु. 8080 से अधिक | ‘वेतन’ का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1616/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 3378/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। |

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात परंतु 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

| वेतनमान प्रतिमाह | मासिक परिवार पेंशन की राशि |
|----------------------|---|
| (1) | (2) |
| रु. 4210 तक | 'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1056/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा। |
| रु. 4211 से रु. 8420 | 'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1262/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा। |
| रु. 8420 से अधिक | 'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1687/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 3521/- प्रतिमाह होगा। |

(घ) 01 मई 2005 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में :-

| वेतनमान प्रतिमाह | मासिक परिवार पेंशन की राशि |
|-----------------------|---|
| (1) | (2) |
| रु. 5720 तक | 'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1435/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा। |
| रु. 5721 से रु. 11440 | 'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1715/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा। |
| रु. 11440 अधिक | 'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2292/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 4784/- प्रतिमाह होगा। |

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके पश्चात परंतु 30 अप्रैल 2005 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस खंड के अनुसार निम्न होंगी :-

(च) 01 मई 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में:-

| वेतनमान प्रतिमाह | मासिक परिवार पेंशन की राशि |
|------------------|--|
| (1) | (2) |
| रु. 7090 तक | 'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1779/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा। |

| | |
|-----------------------|---|
| रु. 7091 से रु. 14180 | 'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2186/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा। |
| रु. 14180 से अधिक | 'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2841/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 5930/- प्रतिमाह होगा। |

टिप्पणी :-

- (1) महंगाई भत्ता अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं होगा।
- (2) उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन से वेतनमान, विनियम 2 के उप खंड (एस) में निर्धारित 'वेतन' तथा विनियम 35 के उप-विनियम (3) की व्याख्या में निर्धारित भत्तों का योग होगा।
- (3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम राशि, कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन की दर के अनुपात में होगी।
- (4) यदि मूल परिवार पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से कम होता है तो पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन दी जाए और ऐसी न्यूनतम परिवार पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। लेकिन, न्यूनतम परिवार पेंशन के अतिरिक्त परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से दिए गए उक्त विनियमों को संयुक्त नोटों और निपटान के लिये सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार, संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर के कामगार संघों तथा अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आलोक श्रीवास्तव
महाप्रबंधक, (एचआरएमडी)

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 दिनांक 29.09.1995 में अधिनियम संख्या 63 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और बाद में प्रकाशित निम्न अधिसूचनाओं के अनुसार संशोधित किया गया, अर्थात् :-

| क्र. संख्या | अधिसूचना संख्या | दिनांक |
|-------------|-----------------|------------|
| 1 | 13 | 27.03.1999 |
| 2 | 71 | 08.04.2002 |
| 3 | 03 | 18.01.2003 |
| 4 | 35 | 28.08.2004 |
| 5 | 26 | 26.06.2010 |
| 6 | 18 | 02.05.2015 |

केनरा बैंक

बैंगलूरु, दिनांक 8 नवंबर 2017

सं. एचआरडब्ल्यूपीएम 10220 78 डीके—धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पढ़े जाने वाले, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, केनरा बैंक के निदेशक मंडल ने केनरा बैंक (अधिकारियों) सेवा विनियम, 1979 में आगे के लिए निम्नलिखित नियमों में संशोधन किया है :-

1. (1) इन विनियमों को केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम 1 नवंबर 2007 से प्रभावी माने जाएंगे बशर्ते इस संबंध में कोई विशेष उल्लेख न किया गया हो।

2. केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 3 में (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित होगा) -

(i) खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

‘(एफ) "परिवार" का अर्थ है अधिकारी का पति या पत्नी, पूरी तरह से निर्भर अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से अपनाए गए बच्चों सहित), अधिकारी पर पूरी तरह से निर्भर और सामान्यतः साथ रहने वाले माता-पिता तथा चालीस प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक विकलांगता वाले भाई या बहन’।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए यदि बच्चों, माता-पिता, भाई या बहन की मासिक आय प्रति माह ₹3500/- से अधिक नहीं हो तो ऐसे बच्चों या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन को अधिकारी पर निर्भर माना जाएगा।

बशर्त कि यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹ 3,500/- प्रति माह से अधिक हो या माता-पिता दोनों की कुल आय ₹3,500/- प्रति माह से अधिक हो, तो माता-पिता को पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर नहीं माना जाएगा।

(ii) खंड (ओ) को हटा दिया जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में -

(i) उप-विनियम (4ए) को हटा दिया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (4ए) को हटाए जाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5) 1 नवंबर 2007 से प्रभावी, प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा:

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

स्केल VII = ₹ 46800 - 1300/4 - 52000

स्केल VI = ₹ 42000 - 1200/4 - 46800

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

स्केल V = ₹ 36200 - 1000/2 - 38200 - 1100/2 - 40400

स्केल IV = ₹ 30600 - 900/4 - 34200 - 1000/2 - 36200

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी

स्केल III = ₹ 25700 - 800/5 - 29700 - 900/2 - 31500

स्केल II = ₹ 19400 - 700/1 - 20100 - 800/10 - 28100

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

स्केल I = ₹ 14500 - 600/7 - 18700 - 700/2 - 20100 - 800/7 - 25700

स्पष्टीकरण-प्रत्येक अधिकारी, जो 31 अक्टूबर, 2007 को लागू होने वाले वेतनमान से अभिशासित होते हैं, इस उप-विनियम में 1 नवंबर, 2007 को चरणबद्ध आधार पर निर्धारित वेतन के पैमाने पर लाए जाएंगे, अर्थात् अन्यथा उपलब्ध कराए गए के अलावा संबंधित चरणों में संबंधित स्केल पहले चरण से और वेतन वृद्धि सामान्य रूप से प्रतिवार्षिक तिथि में देय होनी चाहिए।

(6) इन सभी श्रेणियों में कार्यरत अधिकारियों के लिए जिनकी बैंक को हर समय आवश्यकता होती है, उप विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में -

(ए) उप-विनियम (1) के लिए, निम्न उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार 1 नवंबर, 2007 और उसके बाद से, वेतन वृद्धि निम्नानुसार मंजूर की जाएगी, अर्थात्: -

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में निर्धारित वेतन की तर्ज पर निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन होगी, और वार्षिक आधार पर देय होगी और उस महीने की पहली तिथि से दी जाएगी जिस महीने में देय है;

- (ख) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल - I में अधिकारी जो उच्चतम स्केल तक पहुंचने के बाद मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल- II वेतनमान में चले गए हैं वह प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए चार गतिरोध वेतन वृद्धि जिनमें से पहले दो ₹ 800 और अगले दो ₹ 900 के पात्र होंगे,;

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2007 को जिस अधिकारी ने द्वितीय गतिरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया हो उसे 1 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि और अन्य गतिरोध वेतन वृद्धि 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद द्वितीय गतिरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के छह वर्ष पर मिल जाएगी;

- (ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल-II में अधिकारी जो उच्चतम स्केल तक पहुंचने के बाद मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल- III वेतनमान में चले गए हैं, वे सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों के लिए ₹ 900 प्रति वर्ष की तीन गतिरोध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

बशर्ते कि जिस अधिकारी ने 1 नवंबर, 2007 को प्रथम गतिरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया हो उसे 1 नवंबर, 2007 को अगली गतिरोध वेतन वृद्धि मिल जाएगी और आगामी गतिरोध वेतन वृद्धि 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद प्रथम गतिरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के छः वर्ष पर मिल जाएगी;

बशर्ते कि अधिकारी मूल रूप से मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल III में नियुक्त या पदोन्नत हुआ हो, प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ₹ 900 प्रति वर्ष की चार गतिरोध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे या:

यह भी बताया गया है कि जिन अधिकारियों ने पहले ही दो गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्त की है और 1 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल से अधिक सेवा पूरी कर ली है, 1 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि मिलेगी और 1 नवंबर, 2008 को दूसरी गतिरोध वेतन वृद्धि के छह साल पर चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि मिल जाएगी।

स्पष्टीकरण-इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्च स्तर में इस तरह की वृद्धि पदोन्नति के लिए लागू नहीं होगी और अधिकारी का विशेषाधिकार, अनुलाभ, अधिकार और कर्तव्य उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेगा।

(बी) उप-विनियम (2) में, -

- (i) खंड (ई) के बाद और नोट से पहले स्पष्टीकरण में, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

“(एफ) 1 नवंबर 2007 और उस दिन से, अन्य चीजों के अपरिवर्तनीय रहते हुए, पेशेवर योग्यता वेतन की मात्रा निम्नवत संशोधित होगी: -

सारणी

| | |
|--|--|
| जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान का कनिष्ठ एसोसिएट पास किया है या बैंकरों के भारतीय संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट हैं। | (i) अधिकतम स्केल तक पहुंचने के एक साल बाद ₹ 410 प्रति माह। |
| जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट के दोनों भागों को पास कर लिया है | (i) अधिकतम स्केल तक पहुंचने के एक साल बाद ₹ 410 प्रति माह। (ii) अधिकतम स्केल तक पहुंचने के दो साल बाद ₹ 1030 प्रति माह। |

बशर्ते कि किसी अधिकारी ने भारतीय बैंकर संस्थान से कनिष्ठ एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान से प्रमाणित एसोसिएट (एक या दोनों भाग) की योग्यता अधिकतम वेतन तक पहुंचने के बाद प्राप्त की हो, इस योग्यता को प्राप्त करने की तारीख से पेशेवर योग्यता वेतन की पहली किस्त दी जाएगी और पेशेवर योग्यता वेतन की अगली किस्तों का निर्माण व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त के निर्माण की तारीख के संदर्भ में होगा:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां किसी अधिकारी ने पहले से ही किसी भी योग्यता को प्राप्त कर लिया है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई भी वेतन वृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन को अर्जित नहीं किया है, तो उसे 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि, जो भी बाद में हो व्यावसायिक योग्यता वेतन दिया जाएगा।”;

- (ii) नोट में, खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) अगर 27 अप्रैल 2010 को किसी अधिकारी ने खंड (iv) में निर्दिष्ट किसी योग्यता को प्राप्त कर लिया है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई भी वेतन वृद्धि या पेशेवर योग्यता वेतन को अर्जित नहीं किया है, तो उसे 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि से, जो भी बाद में हो पेशेवर योग्यता वेतन वृद्धि दी जाएगी।”;

(सी) उप-विनियम (3) में, -

(i) खंड (डी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ई) 1 नवंबर, 2007 को और उस दिन से, अन्य चीजें समान रखते हुए, आवास किराया भत्ता सहित निश्चित वैयक्तिक वेतन दर निम्नानुसार होगी और सेवा की पूरी अवधि के लिए अवरोधित रहेंगे: -

सारणी

| वृद्धि घटक (₹) | यथा 01.11.2007 को वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (₹) | देय कुल निश्चित वैयक्तिक वेतन जहां बैंक द्वारा आवास प्रदान की जाती है (₹) |
|----------------|---|---|
| (ए) | (बी) | (सी) |
| 800 | 58 | 858 |
| 900 | 65 | 965 |
| 1000 | 72 | 1072 |
| 1100 | 79 | 1179 |
| 1200 | 86 | 1286 |
| 1300 | 94 | 1394", |

(iii) नोट में, खंड (i) और (ii) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(i) तालिका के स्तंभ(सी) के अंतर्गत खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) के तहत दर्शाए हुए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक द्वारा आवास प्रदान किया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ता के लिए पात्र अधिकारियों को निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन खंड (ई) के अंतर्गत तालिका के निर्दिष्ट स्तंभ (ए) और (बी) के अनुसार कुल राशि होगी और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आवास किराया भत्ता वृद्धि अंतिम वेतनमान विनियम 4 के उप-नियमों (2), (3), (4) या (5) में निर्दिष्ट के अनुसार अर्जित किया हो।";

(iii) नोट के बाद आने वाले खंड (ई) को उप-खंड (v) के रूप में और इसके क्रम में नामित किया जाएगा, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात्: -

"(V) जिस अधिकारी ने उच्चतम स्केल तक पहुंचने के एक वर्ष बाद उपर्युक्त खंड (ए) के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, उसे खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) में उल्लिखित अनुसार निश्चित वैयक्तिक भत्ता/निश्चित वैयक्तिक वेतन मिलेगा।";

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में -

(i) उप-विनियम (3) में, नोट का विलोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4) में, नोट का विलोप किया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम और नोट को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) दिनांक 1 नवंबर, 2007 को या उस तिथि से, त्रैमासिक औसत में 2836 अंकों से ऊपर प्रत्येक चार अंकों की बढ़ोतरी या गिरावट के लिए अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 = 100 वेतन का 0.15% पर महंगाई भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, -

ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ गतिरोध वृद्धि सहित मूल वेतन है;

बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी), (डी), (ई) और (एफ) में निर्दिष्ट पेशेवर योग्यता भत्ता या पेशेवर योग्यता वेतन महंगाई भत्ता के लिए देय होगा।"

6. उक्त विनियम के विनियम 22 में, उप-नियम (1) और (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) 1 नवंबर, 2002 को या उस तिथि से,

(क) जहां एक अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहाँ जिस वेतनमान में उन्हें रखा गया है उसके पहले चरण के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उनसे वसूली जाएगी;

- (ख) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों के अनुसार आवास किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

सारणी

| जहां कार्यस्थल है | देय आवास किराया भत्ता |
|--|-----------------------|
| (1) | (2) |
| (i) मुख्य "ए" श्रेणी की शहरों और समूह 'ए' में परियोजना क्षेत्र केंद्र | वेतन का 8.5% |
| (ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान और समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र केंद्र | वेतन का 7.5% |
| (iii) अन्य स्थान | वेतन का 6.5% |

बशर्ते कि कोई अधिकारी यदि किराया रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसके लिए देय आवास किराया भत्ता नियुक्त वेतनमान के पहले चरण में 1.75 प्रतिशत से अधिक आवासीय सुविधा के लिए दिया गया वास्तविक किराया आवास किराया का अधिकतम 150 प्रतिशत और उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार देय होगा।

(2) 1 नवंबर, 2007 को और उस तिथि से, -

- (ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहाँ जिस वेतनमान में उन्हें रखा गया है उसके पहले चरण के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उनसे वसूली जाएगी;
- (बी) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों के अनुसार आवास किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

सारणी

| जहां कार्यस्थल है | देय आवास किराया भत्ता |
|---|-----------------------|
| (1) | (2) |
| (i) मुख्य "क" वर्ग शहरों और समूह 'क' के परियोजना क्षेत्र केंद्र | वेतन का 8.5 % |
| (ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह 'ख' के परियोजना क्षेत्र केंद्र | वेतन का 7.5 % |
| (iii) अन्य स्थान | वेतन का 6.5 % |

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसके लिए देय आवास किराया भत्ता उस वेतनमान के पहले चरण में 1.20 प्रतिशत से अधिक वेतन में आवासीय सुविधा के लिए दिया गया वास्तविक किराया होगा, उपरोक्त तालिका के स्तंभ (2) के अनुसार उसे देय अधिकतम 150 प्रतिशत आवास किराया भत्ता रखा गया है।

नोट: अपने स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े आवास किराए पर भत्ते के लिए अधिकारियों के दावों को अब से आवास किराया भत्ता के 150 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाएगा।";

7. उक्त विनियम के विनियम 23 में, -

- (i) उप-विनियम (1) में "नवंबर 2002 का पहला दिन", आंकड़ों, अक्षरों व शब्दों के लिए, आंकड़ों, अक्षरों व शब्दों को "नवम्बर 2007 का पहला दिन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (2) में "नवंबर 2002 का पहला दिन", आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए, "नवम्बर 2007 का पहला दिन" आंकड़े, पत्र और शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप-विनियम (3), (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात्: -

"(3) 1 नवंबर 2007 को और उस दिन से, यदि कोई अधिकारी एक क्षेत्र में सेवा कर रहा है जिसे समूह ए या समूह बी में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, तो वह समूह ए या समूह बी के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार ₹ 290 प्रति माह या ₹ 255 प्रति माह के दर पर परियोजना क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता के लिए पात्र होगा।

(4) 1 नवंबर, 2007 को और उस दिन से, यदि एक अधिकारी शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है और यदि उसके एक या अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह सभी बच्चों के लिए अकादमिक वर्ष के अंत तक उत्तरार्द्ध स्थान को रिपोर्ट की तिथि से ₹ 700 प्रति माह के मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता के लिए पात्र होंगे, बशर्ते यदि सभी बच्चों का पूर्व स्थान पर अध्ययन करना बंद हो जाता है तो इस तरह के भत्ते समाप्त हो जाएंगे।

(5) 1 मई 2010 को और उस दिन से, अगर किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, तो वह प्रतिनियुक्त किए गए पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम ₹ 2300 प्रति माह और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है, जहां वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में नियुक्त किया गया था:

बशर्ते कि वह जिस संगठन में तैनात किया गया है वह उसी स्थान पर स्थित है जहाँ उसे अपनी प्रतिनियुक्ति से पहले तैनात किया गया था, उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर अधिकतम ₹ 1200 प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा।

बशर्ते कि एक संकाय सदस्य के रूप में बैंक की प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹ 1200 प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता के लिए लिए पात्र होगा।";

(iv) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात्: -

"(8) 1 नवंबर 2007 को और उस दिन से, यदि कार्य दिवस के दौरान कार्य काल को दो घंटे के न्यूनतम अंतराल में विभाजित किया जाता है, तो अधिकारी प्रति माह ₹165 की दर से विभक्त ड्यूटी भत्ता के लिए पात्र होगा।";

(v) उप-विनियम (10) में,

(क) "नवंबर 2002 के पहले दिन" के आंकड़े, अक्षर और शब्द को, "नवंबर 2007 के पहले दिन" के आंकड़े, अक्षर और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) सारणी के लिए, निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात्:-

सारणी

| स्थान (1) | दर (2) |
|--|-------------------------------------|
| (i) 1000 मीटर और उससे ऊपर, लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मरकेरा टाउन | वेतन का 2% अधिकतम ₹ 550 प्रति माह |
| (ii) 1500 मीटर और उससे ऊपर, लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान | वेतन का 2.5% अधिकतम ₹ 680 प्रति माह |
| (iii) 3000 मीटर और उससे ऊपर वाले स्थान | वेतन का 5% अधिकतम ₹ 1570 प्रति माह |

8. उक्त विनियम के विनियम 24 में, उप-नियम (I) के खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ए) चिकित्सा व्यय- 1 नवंबर 2007 को और उस दिन से, अधिकारी स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकारी के स्वप्रमाण पत्र के आधार पर लेखा विवरण सहित दावा किए गए व्यय के निर्दिष्ट राशि के लिए निम्न सारणी अनुसार पात्र होगा, अर्थात्: -

सारणी

| श्रेणी | प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा |
|--|--|
| कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन श्रेणी | ₹ 5100 या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
| वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यकारी श्रेणी | ₹ 6320 या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |

नोट- (i) किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि किसी भी समय उपर्युक्त उपलब्ध कराई गई अधिकतम राशि की तीन गुना से अधिक नहीं हो या;

- (ii) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने के लिए अर्थात्, नवंबर 2007 और दिसंबर 2007 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, -

- (i) अधिकारी के मामले में अस्पताल शुल्क का 100 प्रतिशत और उनके परिवार के सदस्यों के मामले में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी; जहां सभी मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है या;
- (ii) कामगार कर्मचारियों के लिए 27 अप्रैल 2010 के दिनांकित द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्धारित अस्पताल में भर्ती योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार 1 मई 2010 को और उस दिन से, इस विनियमन के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के खर्चों की प्रतिपूर्ति निम्न तालिका अनुसार निर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप होगी, अर्थात्: -

| | |
|--|---|
| कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल-I और मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल-II एवं III | (i) बेड चार्ज स्वयं - ₹ 700 प्रति दिन परिवार - ₹ 525 प्रति दिन (ii) अन्य शुल्क कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 125% के स्तर पर। |
| वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी IV एवं V और शीर्ष कार्यकारी श्रेणी VI एवं VII | (i) बेड चार्ज स्वयं - ₹ 900 प्रति दिन परिवार - ₹ 675 प्रति दिन (ii) अन्य शुल्क कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 150% के पैमाने पर। |

9. उक्त विनियम के विनियम 25 में, उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्: -

"(2) उप-विनियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यह बैंक के ऊपर निर्भर होगा कि 1 नवंबर 2007 को और उस दिन से, अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने पर, वेतन के पहले चरण में जिसमें उसे पदस्थापित किया गया है उस मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत राशि के बराबर, या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम है, उस पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए

बशर्ते कि जहां इस तरह के फर्नीचर के साथ अधिकारी को निवास प्रदान किया जाता है, उस वेतन स्केल के पहले चरण में मूल वेतन के 0.25 प्रतिशत बराबर अन्य राशि बैंक द्वारा उनसे वसूल की जाएगी:

बशर्ते कि, जहां ऐसी आवासीय सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, बिजली, पानी, गैस और सफाई के लिए शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

10. उक्त विनियम के विनियम 36 में, उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) 1 मई 2010 को और उस दिन से, हिस्टेरेक्टोमी के मामले में 12 महीनों की समय अवधि के भीतर, अधिकतम 45 दिनों तक छुट्टी भी दी जा सकती है।"

11. उक्त विनियम के विनियम 41 में, उप-नियम (4) में, खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(क) विराम भत्ता - 1 मई 2010 को और उस दिन से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्धारित श्रेणी या स्केल में अधिकारी 'प्रतिदिन' विराम भत्ते के लिए कॉलम (2) में निर्धारित की गई संबंधित दर के लिए हकदार होगा, अर्थात्: -

सारणी

| अधिकारियों की श्रेणी/स्केल | प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर | क्षेत्र I | अन्य स्थान |
|----------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| (1) | (2) | | |
| | ₹ | ₹ | ₹ |
| स्केल IV और ऊपर के अधिकारी | 1000 | 800 | 700 |
| स्केल I/II/III के अधिकारी | 800 | 700 | 600 |

बशर्ते स्केल IV और ऊपर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बाहर कार्य करते समय दिया जाने वाला विराम भत्ता प्रति दिन ₹1200 और स्केल I या II या III के अधिकारियों को प्रति दिन विराम भत्ता ₹ 1000 होगा:

बशर्ते यह कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम है लेकिन चार घंटे से अधिक है, विराम भत्ता उपरोक्त दरों का आधा देय होगा।

स्पष्टीकरण- "प्रति दिन" विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन का अर्थ है कि चौबीस घंटे का समय या उसके बाद के किसी भी भाग के लिए, हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय, आगमन का वास्तविक समय और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, "प्रति दिन" का अर्थ आठ घंटे से कम की अवधि नहीं होगी।

12. उक्त विनियम के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

"(4) 1 मई 2010 को और उसी दिन से, स्थानांतरण किए गए अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार एकमुश्त रकम आहरण के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -

सारणी

| श्रेणी | एकमुश्त |
|-----------------------------------|----------|
| शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन | ₹ 12,000 |
| मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन | ₹ 9,000 |

13. उक्त विनियम के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित नियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

"बशर्ते कि 1 मई 2010 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल-I के अधिकारी जो छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग करते हुए, सबसे कम किराया इकोनॉमी वर्ग में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा, जिस मामले में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या तय की गई दूरी के लिए रेलगाड़ी द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया होगा, जो भी कम हो, और मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल II और मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल III के अधिकारी के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के लाभ हेतु समान नियम लागू होंगे, जहां दूरी 1000 किमी से कम हो।"

14. उक्त विनियम के विनियम 45 में, -

- (i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित नियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंकों की सेवाओं में शामिल अधिकारियों के लिए कोई भविष्य निधि नहीं होगी।";

- (ii) उप-विनियम (3) में, खंड (बी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(सी) अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत प्रावरित अधिकारी जो पेंशन योजना का विकल्प नहीं लेते हैं, वह अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत जारी रहेंगे।";

- (iii) उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों को एक निश्चित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जहां अधिकारी वेतन तथा महंगाई भत्ता का 10% का अंशदान करेगा और द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना एफ. सं.5/7/2003-ईसीबी और पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के अनुसार अंशदान पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा अंशदान की समान राशि प्रदान की जाएगी, जैसा समय-समय पर संशोधित हो।"

15. उक्त विनियम के अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के लिए अनुसूची
(विनियम 23 के उप-विनियम (2) को देखें)

1 नवंबर, 2007 से, अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होगा जब तक कि वे पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाए गए हों या संशोधित किए गए हों, जैसा निम्न तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्: -

सारणी

| क्र.सं. | क्षेत्र | भत्ते (₹) | |
|---------|--|--|--|
| | | वेतन ₹ 14,700/- से कम | वेतन ₹ 14,700/- से अधिक |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मिजोरम (क) मिजोरम का चिम्पतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिले में लुंगलेई शहर के आस पास का 25 किलोमीटर का क्षेत्र (ख) मिजोरम के लुंगलेई शहर से लुंगलेई जिले में सर्वत्र 25 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को छोड़कर (ग) मिजोरम के आइजाल जिले में सर्वत्र | 2000 1600 1200 | 2600 2100 1500 |
| 2. | नगालैंड | 1600 | 2100 |
| 3. | अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह (क) उत्तर अंदमान, मध्य अंदमान, छोटा अंदमान, निकोबार और नार्कोडम द्वीपसमूह (ख) दक्षिण अंदमान (पोर्ट ब्लेयर के साथ) | 2000 1600 | 2600 2100 |
| 4. | सिक्किम | 2000 | 2600 |
| 5. | लक्षद्वीप द्वीपसमूह | 2000 | 2600 |
| 6. | असम | 320 | 400 |
| 7. | मेघालय | 320 | 400 |
| 8. | त्रिपुरा (क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र (ख) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र छोड़कर सर्वत्र | 1600 1200 | 2100 1500 |
| 9. | मणिपुर | 1200 | 1500 |
| 10. | अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र (ख) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र के अलावा सर्वत्र | 2000 1600 | 2600 2100 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर (क) कठुआ जिला: नियाबत बनी, मल्हार और मछोडी (ख) उधमपुर जिला: (i) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भामग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल के अलावा (ii) कम्बन तरफ से गोएल तक का क्षेत्र और मोहरे तहसील में केसी तरफ से अर्नास तक का क्षेत्र (ग) डोडा जिला: पद्मेर का इलाका और किशतवार तहसील का नियाबत नोव्गाम (घ) लेह जिला: जिले के सभी स्थान (ङ) बारामुल्ला जिला: (i) संपूर्ण गुरेझ - निराबत, तंगधार अनुमंडल और केरन इलाका | 2000 2000 1600 2000 2000 2000 | 2600 2600 2100 2600 2600 2600 |

| | | | |
|-----|--|------|------|
| | (ii) मतचिल्ल | 1600 | 2100 |
| | (च) पूछ और रजौरी जिला: पूछ और रजौरी जिले के क्षेत्र, पूछ और राजौरी के शहरी क्षेत्र को छोड़कर एवं दोनों जिले में सुंदरबनी और अन्य शहरी क्षेत्र को छोड़कर | 1200 | 1500 |
| | (छ) उपरोक्त (क) से (च) मद में जो क्षेत्र शामिल नहीं है, किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर के अंदर वाले क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा सीमा भत्ता के लिए उनके खुद के स्टाफ के लिए समय-समय पर घोषित क्षेत्र | 1200 | 1500 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | | |
| | (क) चंबा जिला | | |
| | (i) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायत: बडगौन, बजोल, देओल कुग्ती, नयागाम और तुंडाह, गाँव: ग्राम पंचायत जगत की घाटू, ग्राम पंचायत चौहाता की कानरसी | 2000 | 2600 |
| | (ii) उपरोक्त मद (i) में शामिल पंचायतों और गाँवों को छोड़कर भरमौर तहसील | 1600 | 2100 |
| | (iii) भतियात तहसील में इनदरु पंचायत, चौरा तहसील, डलहौजी शहर (बनिखेत सहित) | 1200 | 1500 |
| | (ख) किन्नौर जिला: | | |
| | (i) असरंग, चितकुल और हंगो कुनो/चरंग पंचायत, छोटा खंबा पंचायत के 15/20 क्षेत्र, नाथपा और रुपी, पूह अनुमंडल, उपरोक्त निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र के अलावा | 2000 | 2600 |
| | (ii) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिला | 1600 | 2100 |
| | (ग) कुल्लू जिला: | | |
| | (i) खरगा, कुशवार और सरगा पंचायत सहित निरमंद तहसील का 15/20 क्षेत्र | 2000 | 2600 |
| | (ii) बाहरी-सराज (निरमंद तहसील के जकत-खाना और के बुरौ के गावों को छोड़कर) और (बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबिस का परबना छोड़कर किंतु निरमंद तहसील के जकत-खाना और के बुरौ के गावों सहित) | 1200 | 1500 |
| | (घ) लाहौल और स्पिती जिला: लाहौल और स्पिती का संपूर्ण क्षेत्र | 2000 | 2600 |
| | (ङ) शिमला जिला: | | |
| | (i) कूट की पंचायत, लबाना-सदना, सर्पना और चंडि-बूँदा सहित रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र | 2000 | 2600 |
| | (ii) डोरा-कावल तहसील, रामपुर में दारकलि ग्राम पंचायत, कशपथ तहसील और परगना सहरान की मुनिश, घोरी चैबिस | 1600 | 2100 |
| | (iii) चोपल तहसील और घोरिस, पंजगाँव, पत्सनों, नौबिस और परगना सहरान की तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देवथी ग्राम पंचायत, परगना बाराबिस, कस्बा रामपुर और रामपुर तहसील के रामपुर परगने का घोरी नोग, शिमला शहर और उसके उपनगर (धल्लि, जातोग, कुसुमपट्टि, मशोब्रा, तारादेवी और टुटु) | 1200 | 1500 |
| | (च) कांगड़ा जिला: | | |
| | (i) बड़ा भंगल और छोटा भंगल का क्षेत्र | 1600 | 2100 |
| | (ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और नगरपालिका सीमा के बाहर के निम्नलिखित कार्यालय किंतु धर्मशाला शहर में | 1200 | 1500 |

| | | | |
|-----|--|------|-------|
| | <p>शामिल-महिला आईटीआई, दारी, अभियांत्रिकी कार्यशाला, रामनगर, बाल कल्याण व शहर एवं देश योजना कार्यालय, साकोह, लोअर साकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध पूर्ति योजना, दुगियर, एचआरटीसी कार्यशाला, साधर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आई.पी.एच. उप मंडल, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिन्वा परियोजना, शामनगर।</p> <p>पालमपुर का एचपीकेवीवी कैम्पस सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर, पालमपुर शहर में शामिल किंतु नगरपालिका सीमा के बाहर के निम्नलिखित कार्यालय-एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बानुरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडब्लूडी विभाग, बुंदला, इलेक्ट्रिकल उप-मंडल, लोहना, डी.पी.ओ निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई विभाग, घुग्गर।</p> <p>(छ) मंडी जिला:</p> <p>जोगिंदरनगर तहसील की छुहर घाटी, बगरा के थुनाग तहसील की पंचायतें, चट्टी, छोटधर, गरागुसैन, गतू, गरयास, जंजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवान, खोलानल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थचधर, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक की पंचायत-बिंग, कमलाह, सक्लाणा, तन्यार और तारखोलह, कारसोग तहसील की पंचायतें-बालिधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, माहोग, मेहुंदी, मांज, पेखी, सैन्ज, सरहान और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें-बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा</p> <p>(ज) सिरमौर जिला:</p> <p>बनी, बाखली (पचचड तहसील), भारोग की पंचायत, भरोगभेनेरी (पौनता तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पचचड तहसील) और थाना कासोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरि ट्रैक्ट</p> <p>(झ) सोलन जिला:</p> <p>मंगल पंचायत</p> <p>(ञ) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त मद (क) से (झ) में शामिल नहीं हैं।</p> | 1200 | 1500 |
| | | 1200 | 1500 |
| | | 1200 | 1500 |
| | | 320 | 400 |
| 13. | उत्तराखंड चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले के तहत क्षेत्र | 2000 | 2600" |

विवरणात्मक ज्ञापन

इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की तरफ से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर के अधिकारी के संघ के बीच संयुक्त नोटों के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हस्ताक्षरित विनियमन जो पूर्वव्यापी प्रभाव से दिए गए हैं। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

के विरुपाक्ष

महा प्रबंधक

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र संख्या 15 में दिनांक 14.04.1990 को प्रकाशित किया गया था। बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा अनुवर्ती संशोधन किए गए, अर्थात् -

| क्र. सं. | राजपत्र अधिसूचना सं. | दिनांक |
|----------|----------------------|------------|
| 1. | 42 | 19.10.1996 |
| 2. | 49 | 07.12.2002 |
| 3. | 16 | 16.04.2011 |

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2016

सं. एन-16/2/तेलंगाना/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा तेलंगाना कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तेलंगाना राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

“समय-समय पर कार्यान्वित किये गए तेलंगाना राज्य के क्षेत्रों को छोड़कर, तेलंगाना राज्य के मेडक, महबूबनगर एवं निजामाबाद जिले के राजस्व गांवों के सभी क्षेत्र”

मुहम्मद इरफान
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/2/तेलंगाना/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा तेलंगाना कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तेलंगाना राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र. सं. | जिलों के नाम |
|----------|--------------|
| 1 | अदिलाबाद |
| 2 | खम्मम |

मुहम्मद इरफान
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/1/फरीदाबाद/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित जिला/क्षेत्र में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र. सं. | जिले का नाम |
|----------|-------------|
| 1 | फरीदाबाद |

मुहम्मद इरफान
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/1/राजस्थान/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिले का नाम | क्र.सं. | जिले का नाम |
|---------|-------------|---------|--------------|
| 1 | अजमेर | 15 | जैसलमेर |
| 2 | अलवर | 16 | झालावाड |
| 3 | बांसवाडा | 17 | झुन्झुनु |
| 4 | बाडमेर | 18 | जोधपुर |
| 5 | भरतपुर | 19 | कोटा |
| 6 | भीलवाडा | 20 | नागौर |
| 7 | बीकानेर | 21 | पाली |
| 8 | बूंदी | 22 | राजसमन्द |
| 9 | चित्तौडगढ़ | 23 | सवाई माधोपुर |
| 10 | दौसा | 24 | सीकर |
| 11 | धोलपुर | 25 | सिरोही |
| 12 | डूंगरपुर | 26 | श्री गंगानगर |
| 13 | हनुमानगढ़ | 27 | टोंक |
| 14 | जयपुर | 28 | उदयपुर |

मुहम्मद इरफान
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/1/जे.एंड.के./2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा जम्मू एवं कश्मीर कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिलों के नाम |
|---------|--------------|
| 1 | श्रीनगर |
| 2 | बडगाम |
| 3 | पुलवामा |
| 4 | रियासी |
| 5 | ऊधमपुर |
| 6 | जम्मू |
| 7 | सांबा |
| 8 | कटुआ |

मुहम्मद इरफान
निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 2016

सं. एन-16/4/तेलंगाना/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा तेलंगाना कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तेलंगाना राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिले का नाम |
|---------|-------------|
| 1 | नलगोंडा |
| 2 | वारंगल |
| 3 | करीमनगर |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 15 सितम्बर 2016

सं. एन-16/1/आन्ध्र प्रदेश/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितंबर, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिला/क्षेत्र का नाम |
|---------|---------------------|
| 1 | पूर्व गोदावरी |
| 2 | पश्चिम गोदावरी |
| 3 | कृष्णा |
| 4 | गुंटूर |
| 5 | प्रकाशम |
| 6 | नेल्लोर |
| 7 | विजयनगरम |
| 8 | श्रीकाकुलम |
| 9 | विशाखापटनम |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/2/मध्य प्रदेश/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितंबर, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिला/क्षेत्र का नाम | क्र.सं. | जिला/क्षेत्र का नाम |
|---------|---------------------|---------|---------------------|
| 1 | भिण्ड | 12 | खरगोन |
| 2 | भोपाल | 13 | मन्दसौर |
| 3 | बुरहानपुर | 14 | मुरैना |
| 4 | देवास | 15 | नीमच |
| 5 | धार | 16 | रायसेन |
| 6 | ग्वालियर | 17 | रतलाम |
| 7 | होशंगाबाद | 18 | रीवा |
| 8 | इंदौर | 19 | सागर |
| 9 | जबलपुर | 20 | सतना |
| 10 | कटनी | 21 | शहडोल |
| 11 | खण्डवा | 22 | उज्जैन |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/1/महाराष्ट्र/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिलों के नाम | क्र.सं. | जिलों के नाम |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 1 | ठाणे | 11 | अमरावती |
| 2 | रायगड | 12 | वर्धा |
| 3 | पलघर | 13 | गोंदिया |
| 4 | पुणे | 14 | अकोला |
| 5 | सोलापुर | 15 | चंद्रपुर |
| 6 | कोल्हापुर | 16 | बुलढाणा |
| 7 | सतारा | 17 | औरंगाबाद |
| 8 | सांगली | 18 | नांदेड |
| 9 | नासिक | 19 | धुले |
| 10 | नागपुर | 20 | जलगाँव |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/2/उत्तराखण्ड/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित जिले/क्षेत्र में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

“नैनीताल एवं देहरादून जिले में आने वाले सभी राजस्व ग्राम एवं क्षेत्र (सामान्य) (उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां पर क.रा.बी. अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हो)”।

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/1/बिहार/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितंबर, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिलों के नाम | क्र.सं. | जिलों के नाम |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 1 | पटना | 9 | गया |
| 2 | भागलपुर | 10 | रोहतास |
| 3 | मुंगेर | 11 | सारण |
| 4 | बेगूसराय | 12 | वैशाली |
| 5 | मुजफ्फरपुर | 13 | भोजपुर |
| 6 | समस्तीपुर | 14 | नालंदा |
| 7 | दरभंगा | 15 | बक्सर |
| 8 | कटिहार | 16 | सीतामढ़ी |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/2/राजस्थान/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिले का नाम |
|---------|-------------|
| 1 | बारां |
| 2 | करौली |
| 3 | चुरु |
| 4 | जालौर |
| 5 | प्रतापगढ़ |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/2/कर्नाटक/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितंबर, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | जिला/क्षेत्र का नाम |
|---------|---------------------|
| 1 | बीदर |
| 2 | चिक्कबल्लापुरा |
| 3 | चिक्कमगलूरा |
| 4 | कोडगु |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/1/उड़ीसा/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जून, 2016

ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा उडीसा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उडीसा राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

“अनुगोल, बालेश्वर, बरगढ, भद्रक, बलांगीर, कटक, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, याजपुर, झारसुगुडा, केंदुझर, खोर्द्धा, कोरापुट, मयूरभंज, पुरी, रायगडा, संबलपुर, सुवर्णपुर और सुंदरगढ”।

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 20 अक्टूबर 2016

सं. एन-16/1/असम/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अक्टूबर, 2016 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा असम कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ असम राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| राज्य | जिला | राजस्व केन्द्र |
|-------|--------|--|
| असम | बरपेटा | 1. बरपेटा (नगरपालिका बोर्ड) 2. बरपेटा रोड (नगरपालिका बोर्ड) 3. हॉवली (टाउन कमिटी) 4. पाठशाला (टाउन कमिटी) |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 5 जुलाई 2017

सं. एन-16/1/त्रिपुरा/2017-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2017 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा त्रिपुरा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-2008 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ त्रिपुरा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| राज्य | जिला |
|----------|-----------------|
| त्रिपुरा | पश्चिम त्रिपुरा |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/2/असम/2017-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2017 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा असम कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ असम राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्र.सं. | राज्य | जिला | राजस्व केन्द्र |
|---------|-------|--------|----------------|
| 1 | असम | धेमाजी | धेमाजी (सदर) |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-16/2/त्रिपुरा/2017-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2017 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा त्रिपुरा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-2008 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ त्रिपुरा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

| क्रम सं. | राज्य | जिला | राजस्व केन्द्र |
|----------|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | त्रिपुरा | उत्तर त्रिपुरा | धरमानगर म्यूनिसिपल काउंसिल |
| 2 | त्रिपुरा | सिपाहीजाला | विसालगढ सब-डिविजन |
| 3 | त्रिपुरा | धलाई | अमबासा म्यूनिसिपल काउंसिल |
| 4 | त्रिपुरा | गोमाती | उदयपुर म्यूनिसिपल काउंसिल |

ए. के. साहू
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

PUNJAB NATIONAL BANK
(HEAD OFFICE)

New Delhi, the 28th December 2017

No. HO:PENSION:MISC 2017—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :-

1. (1) These regulations may be called Punjab National Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2017.
(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Punjab National Bank (Employees') Pension Regulations 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), -
In regulation 2, in clause (s), after sub-clause(c), the following sub-clause shall be inserted, namely:—
“(d) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the first day of May, 2005 the basic pay including stagnation increments, if any, and Special Pay, Graduation Pay, Professional Qualification Pay, increment component of Fixed Personnel Pay and Officiating Pay, if any, drawn by the employee during the last ten months of his service in the Bank:

Provided that with effect from 1st day of May, 2005 the provisions of this clause shall have effect in relation to an employee who retired or died while in service on or after 1st day of April, 1998 but before 30th day of April, 2005.”.
3. In regulation 3 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
“(4) (a) join the service of the bank on or after the notified date and on or before the 31st day of March, 2010;”.
(b) after sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-
“(11) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and continue in the service of the Bank as on the 27th April, 2010 provided such employee meets the requirement and comply with the conditions laid down in the settlement;
(12) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and retired after that date and prior to 27th April, 2010 provided such employee meets the requirements and comply with the conditions laid down in the settlement;
(13) were in service of the Bank, prior to the 29th September, 1995 retired after that date and had died in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meets the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement;
(14) were in the service of the bank prior to the 29th September, 1995 and died while in service of the Bank after that date in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meet the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement.”.
4. In regulation 28 of the said regulations, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided further that employees who ceased to be in service on or after the 29th September, 1995 on account of voluntary retirement before attaining the age of superannuation but after rendering service for a minimum period of 15 years in accordance with the Scheme framed in this regard by the Board with the approval of the Government, shall be entitled to join the Pension Fund, subject to the compliance of the terms and conditions mentioned in the Scheme.”.
5. In regulation 36 of the said regulations,-
(a) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that on and from the 1st day of May, 2005 the amount of minimum pension, in respect of an employee, other than a part-time employee, who retired on or after the 1st April, 1998 but before the 31st October, 2002 shall be rupees one thousand and sixty per month and rupees three hundred and fifty five in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale wages, rupees five hundred and thirty in respect of a part-time employee drawing ½ scale wages and rupees seven hundred and ninety five in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after 1st day of April, 1998.”;

(b) after clause (c), the following clause (d) shall be inserted namely:-

- “(d) rupees one thousand four hundred and thirty five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of May 2005 and rupees four hundred and eighty per month in respect of a part-time employee drawing $\frac{1}{3}$ scale of wages, rupees seven hundred and twenty per month in respect of part-time employee drawing $\frac{1}{2}$ scale wages and rupees one thousand and eighty per month in respect of a part-time employee drawing $\frac{3}{4}$ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of May 2005:

Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this clause shall also apply to an employee including a part-time employee who retired on or after 1st November 2002 but on or before 30th April 2005.;

- (e) rupees one thousand seven hundred and seventy nine per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of November 2007 and rupees five hundred and ninety five per month in respect of a part-time employee drawing $\frac{1}{3}$ scale of wages, rupees eight hundred and ninety two per month in respect of part-time employee drawing $\frac{1}{2}$ scale of wages and rupees one thousand three hundred and thirty nine per month in respect of a part-time employee drawing $\frac{3}{4}$ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November 2007.”.

6. In regulation 40, of the said regulations, in sub-regulation (4),-

(i) in clause (a), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “six thousand seven hundred and fifty six”, the words “seven thousand and forty”, had been substituted.;

- (iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005.‘;
- (v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.”

(ii) in clause (b), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “six thousand seven hundred and fifty six”, the words “seven thousand and forty”, had been substituted;

- (iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005.‘;
- (v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

(iii) in clause (c), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “three thousand three hundred and seventy eight,” the words “three thousand five hundred and twenty,” had been substituted.;

- (iv) four thousand seven hundred and eighty three rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005.‘.
- (v) five thousand nine hundred and twenty eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

7. For regulation 48 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely:-

“48. Recovery of pecuniary loss caused to Bank.-

- (1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or for acts done fraudulently during the period of his service:

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations:

Provided also that the departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service.

- (2) No departmental proceedings, if not instituted while the employee was in service, shall be instituted in respect of an event which took place more than four years before such institutions:

Provided that the disciplinary proceedings so instituted shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

- (3) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee.”.

8. In regulation 52 of the said regulations,-

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 34 or regulation 46 apply, a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires.”.

- (b) in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that pension including family pension to those who opted to join the Bank Employees’ Pension Scheme on or after the 27th April, 2010 shall be payable with effect from the 27th November, 2009.”.

9. For Appendix II to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“Appendix II
(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under :-

- (1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who were in the officers’ cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:-

| Scale of basic pension per month (1) | The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2) |
|---|---|
| (i) Upto Rs. 1250 | 0.67 per cent |
| (ii) Rs. 1251 to Rs. 2000 | 0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs. 1250. |
| (iii) Rs. 2001 to Rs. 2130 | 0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs. 2000. |
| (iv) Above Rs. 2130 | 0.67 percent of Rs. 1250 plus 0.55 percent the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs. 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130. |

- (2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who are in the officers’ cadre and who retire on or after the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial

Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

| Scale of basic pension per month (1) | The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2) |
|---|---|
| (i) Upto Rs. 2400 | 0.35 per cent |
| (ii) Rs. 2401 to Rs. 3850 | 0.35 percent of Rs. 2400 plus 0.29 percent of basic pension in excess of Rs. 2400 |
| (iii) Rs. 3851 to Rs. 4100 | 0.35 percent of Rs. 2400 plus 0.29 percent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 percent of basic pension in excess of Rs. 3850 |
| (iv) above Rs. 4100 | 0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs. 4100 and Rs. 3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs. 4100 |

- (3) In the case of employees who retire on or after the 1st day of April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

| Scale of basic pension per month | The rate of dearness relief as a percentage of basic pension |
|----------------------------------|---|
| (i) Upto Rs. 3380 | 0.25 per cent |
| (ii) Rs. 3381 to Rs. 5420 | 0.25 per cent of Rs. 3380 plus 0.21 percent basic pension in excess of Rs. 3380 |
| (iii) Rs. 5421 to Rs. 5770 | 0.25 per cent of Rs. 3380 plus 0.21 percent of the difference between Rs. 5420 and Rs. 3380 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs. 5420. |
| (iv) Above Rs. 5770 | 0.25 per cent of Rs. 3380 plus 0.21 percent of the difference between Rs. 5420 and Rs. 3380 plus 0.12 per cent of the difference between Rs. 5770 and Rs. 5420 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs. 5770. |

Provided that on or from the 1st day of May 2005 in the case of employees who retire on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st October 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner given below:

| Scale of basic pension per month | The rate of dearness relief as a percentage of basic pension |
|----------------------------------|---|
| (i) Upto Rs. 3550 | 0.24 per cent |
| (ii) Rs. 3551 to Rs. 5650 | 0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent basic pension in excess of Rs. 3550 |
| (iii) Rs. 5651 to Rs. 6010 | 0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs. 5650 and Rs. 3550 plus 0.12 of basic pension in excess of Rs. 5650 |
| (iv) Above Rs. 6010 | 0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs. 5650 and Rs. 3550 plus 0.12 per cent of the difference between Rs. 6010 and Rs. 5650 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs. 6010 |

- (4) In respect of employees who retire on or after the 1st day of May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly

average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after 1st day of November 2002 but on or before 30th day of April 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2007, Dearness Relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent of basic pension.

- (5) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with the 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.
 - (6) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.
 - (7) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.
 - (8) Dearness relief is not payable on additional pension.
 - (9) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.”.
10. For Appendix III to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely :-

“Appendix III
(See Regulation 39)

The ordinary rates of family pension shall be as under:-

- (a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers’ cadre and retired before the 1st day of July, 1993:-

| Scale of pay per month (1) | Amount of monthly Family pension (2) |
|-------------------------------|---|
| Upto Rs. 1500 | 30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 375 per month. |
| Rs. 1501 to Rs. 3000 | 20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 percent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 450 per month. |
| Above Rs. 3000 | 15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 600 per month and not more than Rs. 1250 per month. |

- (b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers’ cadre and retired on or after the 1st day of July 1993:-

| Scale of pay per month (1) | Amount of monthly Family Pension (2) |
|-------------------------------|---|
| Upto Rs. 2870 | 30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 720 per month. |
| Rs. 2871 to Rs. 5740 | 20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 860 per month. |
| Above Rs. 5740 | 15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1150 per month and a maximum of Rs. 2400 per month. |

- (c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of April, 1998: -

| Scale of pay per month (1) | Amount of monthly Family Pension (2) |
|-------------------------------|---|
| Upto Rs. 4040 | 30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1015 per month. |
| Rs. 4041 to Rs. 8080 | 20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1212 per month. |
| Above Rs. 8080 | 15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1616 per month and a maximum of Rs. 3378 per month. |

Provided that on and from the 1st day of May, 2005 in respect of the employees (both officers and workmen), other than part time employees, who retired on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st day of October, 2002, the ordinary rate of family pension shall be as under:-

| Scale of pay per month (1) | Amount of monthly Family Pension (2) |
|-------------------------------|--|
| Up to Rs. 4210 | 30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1056 p.m. |
| Rs. 4211 to Rs. 8420 | 20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident |

| | |
|----------------|---|
| | Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1262 p.m. |
| Above Rs. 8420 | 15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1687 p.m. and a maximum of Rs. 3521 p.m. |

- (d) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of the May 2005:-

| Scale of pay per month (1) | Amount of monthly Family Pension (2) |
|-------------------------------|---|
| Upto Rs. 5720 | 30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1435 p.m. |
| Rs. 5721 to Rs. 11440 | 20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 1715 p.m. |
| Above Rs. 11440 | 15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2292 p.m. and maximum of Rs. 4784 p.m. |

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2002 but on or before the 30th April 2005, ordinary rates of family pension shall be in terms of this clause.

- (e) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November 2007:-

| Scale of pay per month (1) | Amount of monthly Family Pension (2) |
|-------------------------------|---|
| Upto Rs. 7090 | 30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1779 p.m. |
| Rs. 7091 to Rs. 14180 | 20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 2186 p.m. |
| Above Rs. 14180 | 15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2841 p.m. and maximum of Rs. 5930 p.m. |

Notes :-

- (1) Dearness relief is not payable on additional family pension.
- (2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of Pay as defined in clause (s) of regulation 2 and allowances as defined in the Explanation to sub-regulation (3) of regulation 35.
- (3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.
- (4) In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension. However, no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

ALOK SRIVASTAVA
GENERAL MANAGER, (HRMD)

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide notification no. 63 published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 29.09.1995 and subsequently amended as under:-

| Sl. No. | Notification No. | Date |
|---------|------------------|------------|
| 1 | 13 | 27.03.1999 |
| 2 | 71 | 08.04.2002 |
| 3 | 03 | 18.01.2003 |
| 4 | 35 | 28.08.2004 |
| 5 | 26 | 26.06.2010 |
| 6 | 18 | 02.05.2015 |

CANARA BANK

Bangalore, the 8th November 2017

No. HRWPM 10220 78 DK—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Canara Bank Officers' Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Canara Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-
 - (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs. 3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs. 3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’
 - (ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

- (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;
- (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs. 46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs. 42000 - 1200/4 – 46800

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs. 30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 25700 - 800/5— 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs. 19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs. 14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.-Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

- (6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs. 800 each and next two Rs. 900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall

get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub-regulation (2),-

(i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

| | |
|---|---|
| Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers | (i) Rs. 410 per month one year after reaching maximum of the Scale. |
| Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers | (i) Rs. 410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs. 1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale; |

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

(c) in sub-regulation (3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

| Increment Component (Rs.) | Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.) | Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.) |
|----------------------------|--|--|
| (A) | (B) | (C) |
| 800 | 58 | 858 |
| 900 | 65 | 965 |
| 1000 | 72 | 1072 |
| 1100 | 79 | 1179 |
| 1200 | 86 | 1286 |
| 1300 | 94 | 1394”, |

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

- “(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank’s accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;
- (iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-
- “(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, -

- (i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;
- (ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;
- (iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-
- “(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.
- Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-
- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance”.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) on and from the 1st day of November, 2002,

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

| Where the place of work is in | HRA payable shall be |
|---|----------------------|
| (1) | (2) |
| (i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A | 8.5% of Pay |
| (ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B | 7.5% of Pay |
| (iii) Other places | 6.5% of Pay: |

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

| Where the place of work is in | HRA payable shall be |
|---|----------------------|
| (1) | (2) |
| (i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A | 8.5% of Pay |
| (ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B | 7.5% of Pay |
| (iii) Other places | 6.5% of Pay |

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 290 per month or Rs. 255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs. 2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs. 165 per month.”;

- (v) in sub-regulation (10),-

- (a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;

- (b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

| Place (1) | Rate (2) |
|--|--|
| (i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town | 2% of pay subject to a maximum of Rs. 550 per month |
| (ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres | 2½% of pay subject to a maximum of Rs. 680 per month |
| (iii) Place with an altitude of 3000 metres and above | 5% of pay subject to a maximum of Rs. 1570 per month”; |

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

| Grade | Maximum limit of reimbursement |
|---|---|
| Junior Management and Middle Management Grade | Rs. 5100 or the amount incurred whichever is less |
| Senior Management and Top Executive Grade | Rs. 6320 or the amount incurred whichever is less |

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

- (ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

- (i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

| | |
|--|--|
| (a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III. | (i) Bed Charges Self – Rs. 700 per day Family – Rs. 525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees. |
| (b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII. | (i) Bed Charges Self – Rs. 900 per day Family – Rs. 675per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”; |

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:
- Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:
- Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.
10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-
- “(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.
11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
- ‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

| Grades/Scales of officers | Major ‘A’ Class cities | Area I | Other Places |
|--------------------------------|------------------------|--------|--------------|
| (1) | (2) | | |
| | Rs. | Rs. | Rs. |
| Officers in Scale IV and above | 1000 | 800 | 700 |
| Officers in Scale I/II/III | 800 | 700 | 600 |

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs. 1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance shall be Rs. 1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours. ’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

| Grade | Lump Sum |
|---|-------------|
| Top Executive and Senior Management | Rs. 12,000 |
| Middle Management and Junior Management | Rs. 9,000”. |

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule to Canara Bank (Officers’) Service Regulations, 1979

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

| Sr. No. | Area | Allowances (Rs.) | |
|---------|--|------------------------|------------------------|
| | | Pay below Rs. 14,700/- | Pay above Rs. 14,700/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mizoram | | |
| | (a) Chimpui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram. | 2000 | 2600 |
| | (b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram. | 1600 | 2100 |
| | (c) Throughout Aizawl District of Mizoram | 1200 | 1500 |
| 2. | Nagaland | 1600 | 2100 |
| 3. | Andaman and Nicobar Islands | | |
| | (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands | 2000 | 2600 |
| | (b) South Andaman (including Port Blair) | 1600 | 2100 |
| 4. | Sikkim | 2000 | 2600 |
| 5. | Lakshadweep Islands | 2000 | 2600 |
| 6. | Assam | 320 | 400 |
| 7. | Meghalaya | 320 | 400 |
| 8. | Tripura | | |
| | (a) Difficult areas of Tripura | 1600 | 2100 |
| | (b) Throughout Tripura except difficult areas. | 1200 | 1500 |
| 9. | Manipur | 1200 | 1500 |
| 10. | Arunachal Pradesh | | |
| | (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh | 2000 | 2600 |
| | (b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas. | 1600 | 2100 |
| 11. | Jammu and Kashmir | | |
| | (a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi | 2000 | 2600 |
| | (b) Udhampur District: (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b). | 2000 | 2600 |

| Sr. No. | Area | Allowances (Rs.) | |
|---------|--|------------------------|------------------------|
| | | Pay below Rs. 14,700/- | Pay above Rs. 14,700/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre. | 1600 | 2100 |
| | (c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil | 2000 | 2600 |
| | (d) Leh District : All places in the District | 2000 | 2600 |
| | (e) Barmulla District | | |
| | (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua | 2000 | 2600 |
| | (ii) Matchill | 1600 | 2100 |
| | (f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts. | 1200 | 1500 |
| | (g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff. | 1200 | 1500 |
| 12. | Himachal Pradesh | | |
| | (a) Chamba District | 2000 | 2600 |
| | (i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata | | |
| | (ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above. | 1600 | 2100 |
| | (iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper). | 1200 | 1500 |
| | (b) Kinnaur District: | | |
| | (i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above. | 2000 | 2600 |
| | (ii) Entire District other than Areas included in (a) above. | 1600 | 2100 |
| | (c) Kullu District: | | |
| | (i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga | 2000 | 2600 |
| | (ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand). | 1200 | 1500 |
| | (d) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti | 2000 | 2600 |
| | (e) Shimla District : | | |
| | (i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda. | 2000 | 2600 |
| | (ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghoris Chaibis of Pargana Sarahan. | 1600 | 2100 |
| | (iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghoris Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu). | 1200 | 1500 |
| | (f) Kangra District: | | |
| | (i) Areas of Bara Bhagal and Chhota Bhagal | 1600 | 2100 |

| Sr. No. | Area | Allowances (Rs.) | |
|---------|---|------------------------|------------------------|
| | | Pay below Rs. 14,700/- | Pay above Rs. 14,700/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar. | 1200 | 1500 |
| | (g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gattoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja. | 1200 | 1500 |
| | (h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract | 1200 | 1500 |
| | (i) Solan District : Mangal Panchayat. | 1200 | 1500 |
| | (j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above. | 320 | 400 |
| 13. | Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts. | 2000 | 2600" |

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

K VIRUPAKSHA
General Manager

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India No.15 dated 14.04.1990.The subsequent amendments were notified vide the following notifications, namely:-

| Sl No | Gazette Notification No | Date |
|-------|-------------------------|------------|
| 1 | 42 | 19.10.1996 |
| 2 | 49 | 07.12.2002 |
| 3 | 16 | 16.04.2011 |

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th August 2016

No. N-16/2/Telangana/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Telangana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following Districts/area in the State of Telangana namely :—

“All areas falling within the revenue villages of Medak, Mahabubnagar & Nizamabad Districts of Telangana State except the areas which have already been implemented from time to time.

MOHD. IRFAN
Director (P&D)

No. N-16/3/Telangana/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Telangana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following Districts/area in the State of Telangana namely :—

| Sl.No. | Name of the Districts |
|--------|-----------------------|
| 1 | Adilabad |
| 2 | Khammam |

MOHD. IRFAN
Director (P&D)

No. N-16/1/Faridabad/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July 2016 as the date from, which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in Faridabad District in the State of Haryana namely :—

| S.No. | Name of the Districts |
|-------|-----------------------|
| 1 | Faridabad |

MOHD. IRFAN
Director (P&D)

No. N-16/1/Rajasthan/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2016 as the date from, which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in following Districts/area in the State of Rajasthan namely :—

| S.No. | Name of the District | S.No. | Name of the District |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| 1 | AJMER | 5 | BHARATPUR |
| 2 | ALWAR | 6 | BHILWARA |
| 3 | BANSWARA | 7 | BIKANER |
| 4 | BARMER | 8 | BUNDI |

| S.No. | Name of the District | S.No. | Name of the District |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| 9 | CHITTAURGARH | 19 | KOTA |
| 10 | DAUSA | 20 | NAGPUR |
| 11 | DHOLPUR | 21 | PALI |
| 12 | DUNGARPUR | 22 | RAJSAMAND |
| 13 | HANUMANGARH | 23 | SAWAIMADHOPUR |
| 14 | JAIPUR | 24 | SIKAR |
| 15 | JAISALMER | 25 | SIROHI |
| 16 | JHALAWAR | 26 | SRI GANGANAGAR |
| 17 | JHUNJHUNU | 27 | TONK |
| 18 | JODHPUR | 28 | UDAIPUR |

MOHD. IRFAN
Director (P&D)

No. N-16/1/J&K/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the J&K Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following Districts/area in the State of J&K namely :—

| S.No. | Name of the Districts |
|-------|-----------------------|
| 1 | Srinagar |
| 2 | Budgam |
| 3 | Pulwama |
| 4 | Reasi |
| 5 | Udampur |
| 6 | Jammu |
| 7 | Samba |
| 8 | Kathu |

MOHD. IRFAN
Director (P&D)

New Delhi, the 1st September 2016

No. N-16/4/Telangana/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Telangana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Telangana namely :—

| S.No. | Name of the Districts |
|-------|-----------------------|
| 1 | Nalgonda |
| 2 | Warangal |
| 3 | Karimnagar |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

The 15th September 2016

No. N-16/1/A.P/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

| S.No. | Name of the Districts/Areas |
|-------|-----------------------------|
| 1 | East Godavari |
| 2 | West Godavari |
| 3 | Krishan |
| 4 | Guntur |
| 5 | Prakasam |
| 6 | Nellore |
| 7 | Viziangaram |
| 8 | Srikakulam |
| 9 | Visakhapatnam |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/2/M.P/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following Districts/area in the State of Madhya Pradesh namely :—

| S.No. | Name of the District | S.No. | Name of the District |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| 1 | Bhind | 12 | Khargone |
| 2 | Bhopal | 13 | Mandsaur |
| 3 | Burhanpur | 14 | Morena |
| 4 | Dewas | 15 | Neemuch |
| 5 | Dhar | 16 | Raisen |
| 6 | Gwalior | 17 | Ratlam |
| 7 | Hoshangabad | 18 | Rewa |
| 8 | Indore | 19 | Sagar |
| 9 | Jabalpur | 20 | Satna |
| 10 | Katni | 21 | Shahdol |
| 11 | Khandwa | 22 | Ujjain |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/1/Maharashtra/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Maharashtra Employees' State Insurance

(Medical Benefit) Rules, 1953 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Maharashtra namely :—

| S.No. | Name of the District | S.No. | Name of the District |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| 1 | Thane | 11 | Amravati |
| 2 | Raigad | 12 | Wardha |
| 3 | Palghar | 13 | Gondia |
| 4 | Pune | 14 | Akola |
| 5 | Solapur | 15 | Chandrapur |
| 6 | Kolhapur | 16 | Buldhana |
| 7 | Satara | 17 | Aurangabad |
| 8 | Sangli | 18 | Nanded |
| 9 | Nashik | 19 | Dhule |
| 10 | Nagpur | 20 | Jalgaon |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/2/Uttarakhand/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttarakhand Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttarakhand namely :—

“All the revenue villages and Areas under Nainital & Dehradun Districts (Excluding areas where ESI Scheme have been brought into force under Section 1(3) of ESI Act, 1948)”

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/1/Bihar/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Bihar namely :—

| S.No. | Name of the District | S.No. | Name of the District |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| 1 | Patna | 9 | Gaya |
| 2 | Bhagalpur | 10 | Rohtas |
| 3 | Munger | 11 | Saran |
| 4 | Begusarai | 12 | Vaishali |
| 5 | Muzaffarpur | 13 | Bhojpur |
| 6 | Samastipur | 14 | Nalanda |
| 7 | Darbhanga | 15 | Buxar |
| 8 | Katihar | 16 | Sitamarhi |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/2/Rajasthan/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely :—

| S.No. | Name of the District |
|-------|----------------------|
| 1 | Karauli |
| 2 | Jalore |
| 3 | Churu |
| 4 | Pratapgarh |
| 5 | Baran |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/2/Karnataka/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

| S.No. | Name of the District/Area |
|-------|---------------------------|
| 1 | Bidar |
| 2 | Chikkaballapura |
| 3 | Chikkamagaluru |
| 4 | Kodagu |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/1/Odisha/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st June, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Odisha Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following Districts/Areas in the State of Odisha namely :—

“Angul, Baleswar, Bargarh, Bhadrak, Balangir, Cuttack, Dhenkanal, Ganjam, Jagasinghur, Jajpur, Jharsuguda, Kendujhar, Khordha, Korapur, Mayurbhanj, Puri, Rayagada, Sambalpur, Subarnapur and Sundargarh.”

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

The 20th October 2016

No. N-16/1/Assam/2016-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st October, 2016 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Assam Employees' State Insurance (Medical Benefit)

Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Assam namely :—

| State | District | All the Areas Falling Under |
|-------|----------|---|
| ASSAM | BARPETA | 1. Barpeta Town (Municipal Board) 2. Barpeta Road (Municipal Board) 3. Howly (Town Committee) 4. Pathsala (Town Committee) |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

The 5th July 2017

No. N-16/1/Tripura/2017-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2017 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tripura Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 2008 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tripura namely :—

| State | District |
|---------|--------------|
| Tripura | West Tripura |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/2/Assam/2017-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July 2017 as the date from, which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Assam Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Assam namely :—

| S.No. | STATE | DISTRICT | ALL THE AREAS FALLING UNDER |
|-------|-------|----------|-----------------------------|
| 1 | ASSAM | DHEMAJI | DHEMAJI (SADAR) |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)

No. N-16/2/Tripura/2017-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2017 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tripura Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 2008 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tripura namely :—

| Sl.No. | State | District | All the Areas Falling Under |
|--------|---------|---------------|-------------------------------|
| 1 | TRIPURA | NORTH TRIPURA | Dharmanagar Municipal Council |
| 2 | TRIPURA | SIPAHIJALA | Bishlgarh Sub-Division |
| 3 | TRIPURA | DHALAI | Ambassa Municipal Council |
| 4 | TRIPURA | GOMATI | Udaipur Municipal Council |

A.K. SAHU
Joint Director (P&D)